

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

जून

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 02-मई, 2016

विषय:- विगत वर्षों में दैवी आपदा के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कराये गये कार्यों पर सृजित देनदारियों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3796/तेरह-आ0प्र0-2015-16 (सि.ख.ह.की सृजित देनदारियां), दिनांक 29.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दैवी आपदा के अंतर्गत सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा विभिन्न स्तरों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कराये गये कार्यों पर सृजित देनदारियां ₹ 64.51 लाख की धनराशि एस.डी.आर.एफ. मद से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 25.04.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-20 की उपधारा-(1) के प्राविधानों के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2011-12 में भारी बारिश एवं बाढ़ आदि से क्षतिग्रस्त नहरों, गूलों व नदियों में तात्कालिक प्रकृति के कराये गये सुरक्षात्मक कार्यों हेतु सृजित देनदारियों के भुगतान शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त ₹ 64.51 लाख (₹ चौसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली गई हो।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन किया गया हो।
3. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
4. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है।
5. जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप से पुष्टि हो जाय।

(4)

6. कार्य की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। अतः जनपद स्तर पर गठित टीम द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा कर लिया जाना आवश्यकीय होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यकीय होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जाय।
- 3- भविष्य में बजट उपलब्ध न होने की दशा में प्रत्येक ऐसे व्यय हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट आदेश पारित कर घटित आपदा, क्षति का अंश एवं उस पर तत्काल व्यय/कार्य की आवश्यकता का विस्तृत औचित्य देकर स्वीकृति प्रदान की जायेगी व उसका डी.डी.एम.ए. से अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि आवंटन का प्रस्तव तीन माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान (दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2016 तक) के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या-44 NP/XXVII-5/2016, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या-1334(1)/XVIII-(2)/16-4(26)/2016 एवं तदुद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 10- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

*[Handwritten signature]*  
30.5.2016

आज्ञा से,  
*[Handwritten signature]*  
(संतोष बड़ोनी)  
उप सचिव